



Neutral Citation No.-2026:AHC:2876

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-45815 वर्ष 2025

हरवीर @ पहलवान आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रशांत कुमार, शिवेंद्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार और राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक ने अपराध संख्या-872 वर्ष 2017, भ०द०वि० की धारा 302, 201, 34 के तहत ज़मानत मांगी, थाना-सिकंदराबाद, ज़िला: बुलंदशहर, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को 2018 के सी.एम.बी.ए. संख्या 13553 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2018 के तहत ज़मानत दी गई थी, लेकिन अनजाने में वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सका, इस प्रकार, उसके खिलाफ 9.9.2024 को गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया था। एक वास्तविक कार्य के रूप में, आवेदक ने 3.11.2025 को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और तब से वह जेल में है।
5. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। निकट भविष्य में परीक्षण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा और किसी भी स्थगन की मांग भी नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

8. आवेदक- हरवीर @ पहलवान, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 7, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)